

संपादकीय

भारत कृषक समाज अप्रैल, 2015 में अपने 60 वर्ष पूरे कर रहा है। अतीत की सुनहरी यादों को याद करते हुए जब इतिहास देख रहा था तो मैंने पाया की 'भारत में कृषि और सामुदायिक विकास में किसानों की संस्थाओं की भूमिका' विषय पर उद्घाटन समारोह में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का संदर्भ देते हुए तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि केवल वित्तीय आबंटन पर ही नहीं बल्कि हमें अपने खून और पसीने से इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होगी। उन्होंने आगे कहा था एक तुला के समान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की प्रगति को समान बनाना होगा ताकि एक समेकित अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। केवल उद्योग से ही हमें सभी वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। किसानों ने ना केवल इन लक्ष्यों की प्राप्ति की बल्कि कृषि उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया। लेकिन आज संतुलन नहीं है, तोल की सुई किसानों की ओर झुकी हुई है।

हमारी कृषि नीति बहुत सक्षम है – लेकिन किसी अच्छे कार्य से नहीं बल्कि बुरे परिणामों के कारण। अब हम अतीत की नीतियों से कैसे निपटे और हम कैसे नई नीति बनाकर यह सुनिश्चित करें की अब वही पुरानी नीति जैसे दुष्परिणाम नहीं होंगे, यही प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। इसका उत्तर वही है कि नीति निर्माण के कार्यों में किसानों को शामिल किया जाए। अगला प्रश्न होगा की किसानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। यह सब हमें सत्तारूढ़ दल के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और आशा करनी चाहिए की ऐसे कार्यों के लिए सरकार किसी राजनैतिक नियुक्ति जैसे किसी प्रॉपर्टी डीलर की नियुक्ति नहीं करेगी और न ही उन किसानों को रखेगी जो नगरों में रहते हैं और नीहित स्वार्थों की ओर से नीतियों की वकालत करते हैं।

सब्सिडी किसानों की समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनके जीवन निर्वाह का स्तर सुधारने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे वह निराशा में शहरों की ओर पलायन न करें। यह सुझाव दिया गया है कि इसी कृषि सब्सिडी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टिके हुए हैं और शहरों की स्थिति अच्छी है तथा देश विखंडित नहीं है।

जैसा नेहरू जी ने कहा था की वित्त आबंटन करना ही प्रयाप्त नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि मौसम की भविष्यवाणी, सब्सिडी तैयार करना एवं नीतियों को लागू करना अति महत्वपूर्ण है न केवल वित्त आबंटित करना। जितना यह सरल नजर आता है उससे कई गुणा जटिल है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं, नहीं हम तैयार नहीं हैं, क्या मैं आज एक चिंतित किसान हूँ ? हाँ मैं हूँ।

कृषि पर वर्ष 2015 के पूर्व-बजट विचार विमर्श में माननीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन/सुझाव

1. कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि अनुसंधान और विकास में 1 प्रतिशत की वृद्धि की जाए और अगले कुछ वर्षों में इसे 2 प्रतिशत कर दिया जाए।
2. कृषि विस्तार की सेवाएँ समाप्त हो चुकी हैं। 5 वर्ष की योजना की घोषणा की जाए जिसमें प्रत्येक 6 गांव के लिए एक कृषि सनात्क को एक एकसटेशन वर्कर के रूप में नियुक्त किया जाए, एक लाख नौकरियाँ दी जाएँ।
3. देश में प्रत्येक भूखंड के लिए एक भूमि कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
4. जैविक पद्धतियाँ, समूचित कीट प्रबंधन, जैविक कीटनाशकों और जैव उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रचार के लिए 10 गुणा पैसा बढ़ाया जाए। आरंभ में 10 प्रतिशत परिवर्तन का लक्ष्य रखें और इससे अधिक लक्ष्य बाद में।
5. विनाशशील जिंसों का उत्पादन बढ़ाना ; अगले 5 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 4 जिले चुने जाएँ। उन जिलों को (पिछड़े क्षेत्र को प्रमुखता) चुनें जिनमें मौसम, भूमि और जल उपलब्धता सुचारू हो। अनाज से संबंधित सभी सरकारी कार्यकर्मों को इन क्षेत्रों में ही सीमित किया जाए।
6. इसके अतिरिक्त स्मॉल फॉर्मर्स बिजनैस कनसॉर्टियम और एनडीडीबी संयुक्त रूप से एक मिशन आरंभ करें जिससे प्याज, आलू और टमाटर की पैदावार अधिक हो, उनका भंडारण और नियंत्रित वितरण किया जा सके।
7. चारे पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए 'फॉडर सीड मिशन' की आवश्यकता होगी।
8. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जैसा ही गन्ना विकास बोर्ड बनाया जाए।
9. आय बढ़ाने और वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु 'कृषि वन विज्ञान' पर बल दिया जाए।
10. देसी नस्ल की कृत्रिम नस्लों को मिलाने के लिए मानकीकरण, कानूनी कार्यक्रम के लिए पैसा दिया जाए ताकि सभी किसान परिवार दूध देने वाले अच्छे पशु रख सकें और उन्हें नजदीक ही पशु चिकित्सा की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँ।
11. पूरे भारत में श्वेत क्रांति हेतु पैसा दिया जाए। फिलहाल दूध देने वाले देसी पशुओं के दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा जाए।
12. गोशाला के लिए पैसा दिया जाए लेकिन उसमें शर्त रखें की उस बैड़े में कुल पशुओं की संख्या का 40 प्रतिशत भाग नर पशुओं का हो।
13. देसी नस्लों के लिए पशु धन मिशन तैयार किया जाए जिसमें सरकार बीमे की राशि अदा करे, यह राशि दुध की मात्रा पर निर्भर होनी चाहिए।
14. लागू होने वाली और प्रस्तावित सभी सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की जाए। अवयवहारिक परियोजना को समाप्त कर दिया जाए।
15. बड़ी परियोजनाओं में पैसा न लगाएँ जैसे रिवर बैसिनस् को आपस में मिलाने का कार्य। इसके स्थान पर विद्यमान सभी सिंचाई की आधारभूत परियोजनाओं की मर्मरत और रख-रखाव के लिए, सभी नहरों को मिलाने तथा वर्तमान सिंचाई के क्षेत्रों हेतु नालि आदि की व्यवस्था करने के लिए फंड दिया जाए।
16. बाढ़ सिंचाई परियोजनाओं में पैसा न लगाएँ, आधाभूत निवेश के रूप में लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्रोत्साहन दें।
17. 10 लाख छोटे-छोटे जल संचय जलाशयों के लिए फंड दें।
18. सभी किसानों को भूमि नमी नापने के सेंसर वितरित करें।
19. बिना किसी सीमा के 0 प्रतिशत शुल्क पर कृषि मशीनरी (टैक्टर नहीं) के आयात की अनुमति दें।

20. सामूहिक कृषि मशीनरी और लिसिंग को अपनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दें। अलग-अलग किसानों के लिए टैक्टर सहित कृषि मशीनरी रखने को प्रोत्साहित न करें। सहकारी समितियों/किसान उत्पादक संस्थाओं को कृषि मशीनरी की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण दें जिसका भुगतान तीन वर्षों में करना हो और यह संस्थाएँ किसानों को लीज पर अपनी सेवाएँ दें।
21. कृषि बाजार यार्ड 'मंडी' की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए फंड दिया जाए और सभी वर्तमान कृषि मार्केट यार्ड्स में संपूर्ण आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
22. शहरी नवीकरण के लिए फंड देते समय शहरों में यह अनिवार्य किया जाए की कुछ संख्या में किसान मार्केट्स के लिए स्थान दिया जाए और आवासीय क्षेत्रों में संडे मार्केट्स के लिए भी स्थान दिया जाए।
23. कृषि जिंगों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो। दीर्घकालिक कृषि आयात निर्यात नीति बनाई जाए। सरकार की अपनी मन मर्जी/विवेक को समाप्त कर देना चाहिए।
24. ताजे फल एवम् सब्जियों पर अधिकतम आयात शुल्क लगाया जाए।
25. आयातित खाद्य तेल पर भी अधिकतम आयात शुल्क लिया जाए। स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
26. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को अधिक पैसा दिया जाए विशेषकर कृषि क्षेत्र हेतु मौसम की स्टीक भविष्यवानी में नवीनता लाने के लिए।
27. किसानों के जौखिम कम करने के लिए कदम उठाए जाएँ जिसके अंतर्गत सभी फसलों के मौसम और मूल्य बीमा के रूप में सरकार 50 प्रतिशत परिमियम दे।
28. आंकड़े इकट्ठे करने और मूल्यांकन करने के लिए 10 गुना अधिक फंड दिया जाए।
29. किसानों को 2 लाख तक दिए जाने वाले ऋण की संख्या दोगुनी की जाए और उस पर केवल 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाए। सबवेंशन (नकद आर्थिक सहायता) नीति सहायक नहीं है, इसे समाप्त किया जाए।
30. कृषि ऋण के आंकड़े संदेहजनक हैं। सही आंकड़ों के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है ताकि ऋण वास्तविक किसानों को ही मिले।
31. ऋण वसूली ट्रिब्यूनल जैसी एक अथॉर्टी बनाई जाए जिससे किसानों के ऋण विवादों का शीघ्र निपटान हो सके।
32. उर्वरक निर्माण एककों को समय पर सब्सिडी दी जाए। लेकिन इसके लिए उर्वरक क्षेत्र को मिलने वाली आर्थिक सहायता की जांच की जाए ताकि सरकारी धन का अधिक भुगतान न हो पाए।
33. नीतियों में भेदभाव – उर्वरक सहकारी संस्थाओं में भेदभाव समाप्त किया जाए – सैक्शन 115 बी.बी.डी. को क्षेत्र बढ़ाया जाए। सहकारी संस्थाओं को भी नीजि निर्माण क्षेत्र की तरह निवेश भत्ता दिया जाए और इन संस्थाओं को भी बाहर से पैसा लेने की अनुमति दी जाए जैसी अन्य कंपनियों को दी जाती है।
34. राज्य और केंद्र के सहकारी बैंकों को पूर्ण समर्थन दिया जाए ताकि वे न्यूनतम पूंजी की मानकों को पूरा कर सकें जिसके लिए पूंजी उपलब्ध करानी होगी नहीं तो सहकारी बैंक बंद हो जाएंगे।
35. लघु कालिक कृषि ऋण देने में 2 प्रतिशत ब्याज की आर्थिक सहायता नबार्ड द्वारा उन बैंकों को नहीं दी जाती जो दोबारा ऋण देते हैं। दोबारा लिए गये ऋण के भाग पर ब्याज सबवेंशन की सुविधा दी जाए।
36. नबार्ड द्वारा इन बैंकों को 2.50 प्रतिशत की दर से दोबारा वित्त देना चाहिए जैसे इस योजना के आरंभिक स्तर पर लागू होता है।
37. भूमि के आकार के अनुपात में सही आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई जाए। किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देना एक सकारात्मक उपाय हो सकता है किंतु इसमें किसानों के हितों पर आंच नहीं आनी चाहिए।
38. ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई के केन्द्रीय मंत्रालयों को मिलाकर एक शक्तिशाली मंत्रालय बनाया जा सकता है।

39. नियम लागू करने और सरल कारोबार करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जैसे ही एक 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार' की नियुक्ति की जाए ताकि विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों की निगरानी, संकलन और समनव्य हो सके जिससे आरंभ से ही निचे के स्तर पर परिणाम दिखने लगेंगे।

श्री प्रताप नारायण – पूर्व महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया

उद्योग परिप्रेक्ष्य पर विचार करने का समय

उर्वरक की कीमत और आर्थिक सहायता पर होने वाले संपूर्ण वार्तालाप में प्रायः यह भूल जाते हैं कि उर्वरक उद्योग का मूल मामला क्या है। इस उद्योग, इस जिनस के उत्पादक की भूमिका और स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उर्वरक के संदर्भ में तीन पक्ष शामिल हैं ; किसान जो कुछ कीमत ही चुका सकते हैं, सरकार जो आर्थिक सहायता का बोझ उठा सकती है या नहीं उठा सकती, और उद्योग जो व्यावहारिक होने पर ही बना रह सकता है। इन तीन हितों में से कोई एक दो अन्य पर प्रभाव डालता है। यदि किसान इसकी कीमत नहीं चुका सकता तो सरकार को हस्तक्षेप करना होगा और सब्सिडी देनी होगी। यदि सरकार सब्सिडी नहीं देती और उद्योग को भी बनाए रखना है तब किसान को उर्वरक की पूरी लागत चुकानी होगी। ऐसे में आज रु. 5,300/- प्रति टन बिकने वाला यूरिया रु. 18,000/- प्रति टन बिकेगा। ऐसा कोई जादू का फॉर्मूला नहीं है जिसमें किसान पूरी कीमत न दे, सरकार सब्सिडी न दे तो भी उद्योग बना रहे।

जहां तक इस उद्योग का संबंध है, जैसे किसी को वर्ष 1978 में रेलवे से उर्वरक में स्थानांतरित किया गया हो, मैंने देखा है कि अतित में डाली गई नींव अब हिलने लगी है क्योंकि सब्सिडी के कारणों को समझने में बहुत कमियां आ चुकी हैं। 1960 और 1970 के दशकों में अनाज की कमी के कारण भारत को पी.एल. 480 का आयात करके अपना पेट भरना पड़ा। उन दिनों भूखमरी की जैसी स्थिति थी। उस समय अच्छी पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की अनिवार्यता महसूस की गई।

1970 के दशक में ईंधन के मूल्य बढ़ने के कारण उर्वरक के मूल्य बढ़े इसके परिणाम स्वरूप उर्वरकों की खपत कम हो गई। कम मांग के कारण उर्वरक उद्योग पर बुरा असर पड़ा। तब सरकार ने निर्णय लिया कि उर्वरकों का मूल्य उतना रखा जाए जितना किसान वहन कर सके और आयात की लागत और उत्पादन की लागत तथा भारत में वितरण की लागत के अंतर का सब्सिडी के रूप में भुगतान करे। जहां तक आपूर्ति का संबंध था आयात या वितरण के भाव अलग से नियत किए जाते थे और उन दोनों के बीच के अंतर का भुगतान कर दिया जाता था। 6 लाख गांव में 13 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ रु. की आर्थिक सहायता दी गई।

यह सब्सिडी यूरिया पर नहीं बल्कि फॉसफोरस के लिए शुरू की गई थी क्योंकि आयातित कच्ची फॉस्फेट के मूल्य बढ़ गए थे। सरकार ने यूरिया के मूल्य नियंत्रित करने का निर्णय लिया और 1,200 रु. प्रति टन की दर से फॉस्फेट पर सब्सिडी दी जानी थी। प्रश्न यह था कि यह सब्सिडी किसे मिलनी चाहिए ? सी. सुब्रमणियम, खाद्य एवम् कृषि मंत्री ने कहा यह सब्सिडी उद्योग को दी जाएगी ताकि प्रशासन की लागत में कमी हो।

इस सब्सिडी के परिणाम 20-22 वर्षों के बाद दिखे। उदाहरण के लिए 1976 में न्यूट्रिएंट उत्पादन 8.5 मिलियन टन था जो 1999-2000 में बढ़कर 10.87 मिलियन टन हो गया। इसी प्रकार से 1970 में नाइट्रोजन का उपयोग 2 मिलियन टन था जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर लगभग 12 मिलियन टन हो गया। खाद्य उत्पादन 111 मिलियन टन से बढ़कर 209 मिलियन टन हो गया। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया और भूखमरी की स्थिति से भी निकल गया। इस सफलता में कुछ असफलताएँ भी देखने में आईं।

लोग भूल गए कि यह सब्सिडी क्यों आरंभ की गई थी। धीरे-धीरे सब्सिडी कम करने के स्थान पर सरकार ने इसे स्थाई बना दिया। 1992 में सरकार ने एक गलती और करी, घोषणा कर दी की फॉस्फेट और पौटेशियम अनियंत्रित कर दिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में तब कार्य करने और प्रताप राव भौंसले संसदीय समिति का एक सदस्य होने के नाते मुझे सूचित किया गया कि तत्कालिक वित्तमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 10 प्रतिशत तक यूरिया के भाव कम करने और फॉस्फेट और पोटाश को डिकंट्रोल करने का प्रस्ताव रखा है। मैंने उन्हें परामर्श दिया कि कुछ भी डिकंट्रोल न करें क्योंकि 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। मैंने उन्हें फॉस्फेट और पोटाश डिकंट्रोल न करने की प्रार्थना की जिससे सब्सिडी बड़ी थी, फिर भी यूरिया को डिकंट्रोल किया जा सकता है। उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया लेकिन अपनी गलती का एहसास 15 दिनों में ही कर लिया इसके पश्चात समाधान के रूप में सरकार ने राज्य सरकारों को 1,000 रु. प्रति टन डीएपी और एमओपी की सब्सिडी देने का निर्णय लिया ताकि इसे सीधे किसानों को दे दिया जाए।

इस कदम का परिणाम 2 महीने में ही आपूर्ति बंद हो गई क्योंकि कोई सरकारी मशीनरी नहीं थी जो किसानों को इन सुविधाओं और साधनों का वितरण कर पाती। बाद में राज्य सरकारों ने उद्योग से बैठकें की और उनसे मूल्य कम करने के लिए कहा ताकि सरकार उनके खाते में सब्सिडी ट्रांसफर करे। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का उपभोग बढ़ा जबकि पी एण्ड के का उपयोग घट गया जिस कारण असंतुलन हो गया। वर्ष 1996-97 में नई सरकार ने पी एण्ड के की भी धीरे-धीरे सब्सिडी बढ़ाई।

यूरिया में कृत्रिम परिवर्तन करने से उद्योग जगत पर बुरा प्रभाव पड़ा और पिछले 15 सालों में कोई भी नया प्लांट नहीं लगा। इस कारण यूरिया के आयात पर निर्भरता बढ़ गई। लोग गुलाटी साहब कि बात करते हैं कि 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को जाती है और बाकि 48 प्रतिशत ही किसानों को। मैं ऐसा नहीं समझता, यदि उद्योग के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए जाएं और उपकरणों के मूल्य भी नियंत्रण में रखें तो उद्योग जगत कैसे लाभ कमा सकता है।

यदि 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को दी तो यह किसी और क्षेत्र के लिए होगी। लोगों ने इस सब्सिडी की गणना आयात मूल्य से करनी शुरू की यह कहते हुए की यदि आयात शुल्क को कम कर दिया जाए तो सब्सिडी किसानों को ही मिलेगी लेकिन यदि आयात से अधिक मूल्य होगा तो उद्योग को सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यह भूल गए कि गैस निर्यात करने वाले देश में गैस का मूल्य 1 डॉलर प्रति मिलियन बीटीयू था जबकि भारत में गैस और नाफता ईंधन का मूल्य बहुत अधिक था। इस प्रकार इन मूल्यों की तुलना करना उचित नहीं है।

दूसरी गलती तब हुई जब भारत आत्मनिर्भर था और उसे आयात नहीं करना था तब भी मूल्य निर्धारण होता रहा। जब भी ईंधन का आयात बढ़ा तो सब्सिडी भी बढ़ी और वैसे ही चलता रहा। नीति निर्माता सब्सिडी कम करने पर सहमत थे लेकिन उन्होंने सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। आंकड़े दर्शाते हैं कि यूरिया के मूल्य स्थिर रहे जबकि नाफता के मूल्य 700 रु. प्रति टन से 58,000 रु. प्रति टन तक बढ़ गए। ऐसे में लागत की वसूली कहां से होती ?

ईंधन के मूल्यों की तरह और अन्य मूल्यों की तरह ही जिनका भुगतान डॉलर में किया जाता है, बढ़ने से रूपये का अवमूल्यन कई गुणा हो गया। रेल भाडा बढ़ने से भी उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। लोग उसी मूल्य पर यूरिया लेना चाहते थे और कहने लगे कि इतनी मात्रा में सब्सिडी को बोझ सरकार नहीं उठा सकती। यह गलत धारणा है कि भारत में अनाज का बफरस्टॉक और आत्मनिर्भरता है। अन्य मामलों पर भी विचार करना चाहिए। प्रति व्यक्ति कैलोरी की मात्रा कम हो चुकी है क्योंकि भारत के गरीब लोग इन मूल्यों पर भी अनाज नहीं खरीद सकते, भारत और चीन के नाईट्रोजन उत्पादन की तुलना करें तो भारत 12 मिलियन टन वार्षिक जबकि चीन 41 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन करता है। चीन भारत से भी बढा आयातक तथा किंतु आज प्रमुख निर्यातकों में से एक है।

भारत के 4.37 मिलियन टन वार्षिक फॉस्फेट उत्पादन की तुलना चीन के 14 मिलियन टन वार्षिक से करना चाहिए। भारत में न्यूट्रिएंट का उपभोग 165 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर कृषि भूमि पर है जबकि चीन लगभग 400 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर कि दर से उपभोग कर रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप उत्पादकता में सुधार हुआ। भारत का वर्तमान धान उत्पादन 305 मिलियन टन है जबकि चीन का 525 मिलियन टन। प्रति हैक्टेयर फसल का अंतर भी 2,800 किलोग्राम से 5,700 किलोग्राम तक है। इस प्रकार यह कहना कि भारत में उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है बिलकुल गलत है।

आमतौर पर लोग कहते हैं कि सब्सिडी का लाभ अमीर किसानों को जाता है जिनके पास 10 हैक्टेयर से अधिक भूमि है। केवल 1 प्रतिशत किसानों के पास 10 हैक्टेयर से अधिक और 64 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से भी कम भूमि है। यह भी गलत धारणा है कि अमीर किसान अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। किंतु आंकड़े दर्शाते हैं कि मझौले किसान ही अधिक उर्वरक का उपयोग करते हैं क्योंकि उनके पास नवीनतम मशीनें, सिंचाई सुविधाएँ नहीं होती और तकनीकी ज्ञान की भी कमी होती है। अमीर किसानों के पास तकनीकी, अच्छी मशीनें, सिंचाई की अच्छी सुविधाएँ होती हैं और उर्वरक उसमें छोटी भूमिका ही निभाता है।

फिर भी जब बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है तो यदि अमीर किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो देश में अतिरिक्त अनाज के भंडार कहां से आएंगे ? यह मात्रा उन मझौले किसानों से नहीं आती जो अपने द्वारा उगाई गई फसल का स्वयं ही उपयोग करते हैं। खरीद मूल्य में वृद्धि होने से खाद्य सब्सिडी में भी वृद्धि होगी जिस कारण गरीब लोगों की पहुंच से अनाज दूर होता जाएगा।

कहा जाता है कि भारतीय उद्योग असक्षम है। डॉ० गुलाटी के आंकड़े की 52 प्रतिशत सब्सिडी उद्योग को जाती है यह गलत ब्यान है किंतु इसका बखान हर स्थान पर होता है। भारतीय उद्योग की क्षमता, ताकत और उसके योगदान को भुलाने का प्रयास किया जा रहा है जबकि जिंसों का उत्पादन कई गुणा बढ़ा है। उर्जा उपभोग में सक्षमता को 2 मानदंडों से देखा जा सकता है, उत्पादन का प्रति टन उपभोग (जिसे तोडा-मरोडा नहीं जा सकता) भारतीय गैस आधारित प्लांट की 8.29 जीसीएएल प्रति टन अमोनिया है। विकसित देशों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है जहां से यह तकनीक आयात की गई है। दूसरा, मानदंड जल उपभोग का है, यह भी 1990 के दशक के आंकड़ों से 50 प्रतिशत कम है। इस प्रकार भारतीय उद्योग को असक्षम कहना निराधार है।

इस वार्तालाप में एक अनय आयाम जोडा गया है कि सब्सिडी के वास्तविक लाभ लेने वाले वे लोग हैं जो औजारों और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। जैसा पहले बताया गया है तेल कंपनियां सब्सिडी का बहुत बडा भाग गटक जाती हैं और करोड़ों का लाभ कमा रही है। एक तरफ तो हम सब्सिडी बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ टैक्स

बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए गैस के मूल्य रॉयल्टी, टैक्स और आयात शुल्क के अनुसार निर्धारित होते हैं। यह टैक्स आम जनता को ही चुकाने पड़ते हैं लेकिन उर्वरक उद्योग ही आंखों में क्यों चुभता है। निष्कर्ष है कि ऐसा कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जिसमें किसान पूरा मूल्य न दे, सरकार सब्सिडी न दे लेकिन उद्योग चलता रहे। आयात के बारे में एक अन्य बात यह है कि पूरे विश्व में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। यूरोपियन यूनियन, जापान, अमेरिका जहां पर प्रति व्यक्ति, प्रति हैक्टेयर का उत्पादन भारत से भी कम है, वहां पर एक्सपोर्ट को सब्सिडी दी जाती है और उन किसानों को अधिक लाभ मिलता है जिनके पास बड़े-बड़े खेत होते हैं। व्यावहारिक उद्योग के वकीलों का कहना है कि उद्योग की समस्या आयात से हल होगी तो उद्योग के पास अन्य क्या विकल्प है।

इसके लिए दो समाधान हैं। पहला, यदि सरकार सब्सिडी नहीं देना चाहती तो इसे उद्योग को आजाद कर देना चाहिए और यदि सब्सिडी देना चाहती है तो यह सीधे किसानों को दी जा सकती है। सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह उद्योग को मुक्त कर दे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एनपीटी अनुपात के लिए यूरिया को एनबीएस सब्सिडी के अंतर्गत लाया जाए नहीं तो इसे मूल्य बढ़ाने चाहिए ताकि धीरे-धीरे सब्सिडी कम होती जाए।

उद्योग की निर्भरता उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। सब्सिडी कम करने से महत्वपूर्ण औजारों, मशीनरी की लागत में वृद्धि हो जाती है। किंतु सब्सिडी में अनियंत्रित वृद्धि से अधिक टैक्स लगाने पड़ते हैं और समान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता की भारत में ही अनावश्यक टैक्स और शुल्क लगाए जा रहे हैं जबकि सरकार सब्सिडी भी दे रही है। कृषि मूल्यों को मुद्रास्फीति के अनुसार नियमित रूप से समायोजित करना चाहिए।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति को रिवाईव करना और फिक्की के ई.डी. पद को बनाना बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। समय आ गया है कि तर्कसंगत नितियां बनाई जाएं और अस्थायी उपायों को बंद किया जाए तथा बहुत से ऐसे उपाय भी किए जाएं चाहे इसके परिणाम अच्छे न हों लेकिन न्यूट्रिएंट जैसे आवश्यक तत्वों के उत्पादन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए।